[Smt. Sushila Shankar Adivarekar]

win the commanding heights of the economy. Unless and until this is done, unless the public sector comes into the picture, the economy cannot' be improved. Before I conclude, I would like to say again, I would like to make a womanly appeal, to the Finance Minister, that only when the public undertakings start producing mass consumption goods and other essential commodities, we will be able to have some control over price and supply. By this, we will also be able to keep under check and imder control the manipulations of the private enterprise. On the whole, I think, the Finance Minister has done a very good job in bringing forward this Budget and raising the hopes and aspirations of the people.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Approirriation Railways (No. a) BiU, 1980

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report to the Hct,e the following message received from^ the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha: —

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation Railways (No. 3) Bill, 1980, as passed by Lok Sabha, at its sitting b-sld On the 3rd July, 1980.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

CLARIFICATIONS IN RELATION TO STATEMENT BY MINISTER REGARDING NEWSPRINT ALLOCATION POLICY, 1980-81

श्रीजगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में काफी होशियारी से एक वाक्य लिखा है । आप ने लिखा है कि हाई सीज और गोडाउन में जो कागज होगा उसके अन्तर को कम किया जायेगा, "हम ने हाई-सीज बिक्री के मूल्य को बन्दरगाहों पर बफर स्टाक के बिक्री के मूल्य के उतना बराबर करने का निर्णय लिया है जितना न्यायसंगत होगा ।" आभास सामान्य आदमी को यह मिलेगा कि आप कीमतें कम कर रहे हैं, लेकिन है इस का उलटा । आप जानते है कि जो हाई सीज पर कागज है वह सस्ता होता है और बफर स्टाक का मंहगा होता है क्योंकि, जैसा आपने वक्तव्य में कहा है, उस पर टैक्स लगते हैं । साठे साहब गर्दन हिला रहे हैं । अगला वाक्य पढ़ देता हूं—"अखबारी कागज पर बिक्री-कर के बोझ को दूर करने के उपायों की भी वित्त मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जा रही है ।" इस वाक्य से लगता है कि सेल्स टैक्स कम कर दें । लेकिन इससे कहीं यह बात साफ नही होती कि वे बफर स्टाक के मूल्य कम करेंगे या हाई सीज़ के । हाई-सीज़ पर जो कागज लिया जाता है उस पर 1 परसेंट सर्विस चार्ज लेते हैं । आपने इस वक्त 122 करोड़ 1979-80 के लिए रखा है । इसका मतलब है कि 1 करोड़ 2 लाख रुपया तो आप केवल सर्विस चार्ज ले लेंगे । एस टी सी अन्य चीजों पर भी कमाती है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1 परसेंट सर्विस चार्ज लेकर कितना खर्च करते हैं वास्तव में कागज के ऊपर क्यों कि सरकार अकेले कागज के लिए ही तो सब इन्तजाम नहीं करती, और चीजों के लिए भी करती है । तो यह चार्ज कम होना चाहिए '

दूसरे इस वक्तव्य में नेपा के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है । नेपा का मूल्य सस्ता दीखता है, लेकिन सस्ता नहीं है । उस का वेट